THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Information had been received by the Government sometime ago that certain traders in different parts of the country were importing toners used in the printing industry and in photo copying machines by under-invoicing their values. Information was also to the effect that these goods are mis-declared as carbon black. On enquiry, some cases of suspected under valued imports of toners at Bombay and Madras have come to notice. The matter is being examined further.

**Demand for Reducing duty on hard coke**

933. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a demand of the State Electricity Board and the industries that the duty on hard coke should be reduced from 80 per cent to 25 per cent; and

(b) if so, what is the reaction of the Government thereo?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) There is no demand from State Electricity Boards for reduction of import duty on hard coke. However, demand for reduction of import duty on coke from 85 per cent to 25 per cent has been received from the industries of ferro alloy, zinc and lead, foundries etc. The demand for reduction of import duty on coke has been considered but has not been acceded to.

**स्टेट बैंक आफ इन्दौर में व्याप्त भ्रष्टाचार**

934. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1993 को "इन्दौर समाचार" के अंक 46 में "स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्टेट बैंक आफ इन्दौर में व्याप्त भ्रष्टाचार का केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराये जाने की कोई संभावना है; यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) जांच के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि वे सभी खाते, जिनका हवाला समाचार में दिया गया है, उन्हें आवश्यक सर्वेक्षण तथा उपयुक्त जमानतों/गारन्टियों के पश्चात् ही ऋण सुविधायें स्वीकृत की गई थीं । तथापि, इनमें प्रत्येक कुछेक खाते पुनर्वास/वसूली में अनेक स्तरों पर कमजोर/रुग्ण हो गए हैं । बैंक ने ऐसे सभी मामलों के बारे में अपने निदेशक मण्डल/भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार को सूचित किया है । वसूली प्रयासों की प्रगति भी बैंक द्वारा अपने निदेशक मण्डल के समक्ष रखी जाती है । अतः बैंक का यह विचार है कि इन परिस्थितियों/सामग्री को देखते हुए किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

**Income Tax raids on companies**

935. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of income tax raids conducted Statewise during 1993 till date;

(b) the names of the companies/establishments etc. on which income tax raids were made;

(c) what is the outcome of these income tax raids; and